IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

ग्रामीण एवं कृषि संरचना – योजना एक पहल

मलसिंह मोरी

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) , भाासकीय महाविद्यालय, अंजड़ जिला बड़वानी (म.प्र.)

संक्षेपिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राचीन और आधुनिकीकरण दोनों व्याप्त है । आज भी 68 प्रति ात आबादी गावों में निवास करती है जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है । कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है । भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधरना है तो वहॉ की कृषि का विकास करना चाहिए । विकसित दे ा कृषि के स्थान पर उद्योगो पर अधिक निर्भर करते है । सभी खाद्यान्नों की कुल उत्पादिकता 1960–61 में 701 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी जो 2014–15 में बढ़कर 2070 कि.ग्रा. हो गई अर्थात इसमें 3 गुणा बड़ी वृद्धि हुई । पिछले 60 वर्षो में सबसे अधिक उत्पादकता में वृद्धि गेहूँ में उत्पादकता में हुई जो 1960–61 में 851 से बढ़कर 2014–15 में 2872 कि.ग्राम प्रति हेक्टर हो गई। आर्थिक क्षेत्र में कृषि तथा ग्रामीण विकास को योजना का आधार बनाया जाना चाहिए गांव एवं शहर के असंतुलन को रोका जाना चाहिए ।

भाब्द कुंजी– संरचना, ग्रामीण, कृशि विकास, मानसून, सफलता, उद्योग, लक्ष्य, तकनीक।

प्रस्तावाना :– भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राचीन और आधुनिकीकरण दोनों व्याप्त है । आज भी 68 प्रति ात आबादी गावों में निवास करती है जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है । हालॉकि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 52 प्रति ात से घटकर 13.9 प्रति ात हो गया है । कृषि संरचना के पिछड़ेपन के साथ–साथ बहुलता में गरीबी एक लक्षण है । भारत में आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद भारतीय कृषि की एक वि ोषता यह है कि यहॉ पर अधिकां ा उत्पादन पुरानी तकनीक से ही होता है जिसमें खुरपी और लकड़ी के हल की ही प्रमुखता है इसमें सुधार होता जा रहा है । कृषक आधुनिक पद्धति अपनाने लगे है । कृषि के महत्व तथा उसकी वि ोषताओं को देखते समय आर्थिक विकास में कृषि को पिछली पंचवर्षीय योजना में अधिक महत्व दिया जाता रहा है । कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है । इसके विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता निर्भर करती है । **सर जॉन रसेल** ने भारतीय कृषि व्यवस्था के विषय में लिखा है । '' यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधरना है तो वहॉ की कृषि का विकास करना चाहिए ।'' यहॉ यह स्पष्ट होना आव यक है कि कृषि क्षेत्र में आय तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है । दुनिया के विकसित दे ा कृषि के स्थान पर उद्योगो पर अधिक निर्भर करते है । कृषि में जोखिम की मात्रा सर्वाधिक होती है । भारत में लगभग 28 प्रति ात भाग ही अभी तक सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकता है । वि ोषज्ञों का मत है कि सम्पूर्ण सिंचाई के साधनों जिनमें बड़े, मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाएं सम्मिलित की जाती है । को उपलब्ध कराये जाने के बाद भी लगभग 51 प्रति ात भू–भाग जिसका कि कृषि उत्पादन में उपयोग होता है । मानसून पर ही निर्भर रहेगा । मानसून भारत वर्ष में अनिश्चित रहता है । वर्तमान में 70 प्रति ात उपजाऊ भूमि का भाग वर्षा पर ही निर्भर है । हिमालय से निकली नदियों को छोड़कर बाकी नदियॉ वर्षा पर निर्भर करती है ।

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

अतः यह माना जाता है कि कृषि उत्पादन में निश्चितता औद्योगिक उत्पादन के मुकाबले कम रहती है । इससे आय कम तथा अनि चत रहती है । ऐसी स्थिति में कृषि विकास पर वि ोष स्थान दिया जाना आव यक होता है । इसे हम संरक्षित उद्यम कहे तो अधिक उपर्युक्त होगा ।

आर्थिक क्षेत्र में कृषि तथा ग्रामीण विकास को योजना का आधार बनाया जाना चाहिए गांव एवं शहर के असंतुलन को रोका जाना चाहिए । ताकि कृषि एवं ग्रामीण विकास की विनिर्मित पूॅजी शहरी उद्योग में आगे और न जायें ।

उद्देश्य :–

- कृषि विकास का अध्ययन करना ।
- संरचना के बारे में जानना ।
- योजनाओं का अध्ययन करना ।
- उद्योग एवं बाजार में महत्व का पता लगाना ।
- ग्रामीण कृषि को जानना ।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत भोध में द्वितीयक समंको का संकलन कर तालिका के माध्यम से वर्गीकरण, वि लेषण एवं निर्वचन से निष्कर्ष निकाला गया है।

ग्रामीण कृषि संरचना :– मनुष्य के सामाजिक जीवन का प्रारम्भ ग्रामों से ही हुआ । विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य का जीवन घूमन्तू था । स्थायी कृषि करने की विधि के विकास के साथ ही मनुष्य घूमन्तू जीवन त्याग कर एक नि चत स्थान पर बसने लगे । मनुष्यों की यह प्रारम्भिक बसाहट ग्राम कहलाएं । ग्राम आज भी है , जहा मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है । ग्रामीण कृषि मे समाज विभिन्न रूप में स्वतंत्र पाए जाते है । भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि यहां ग्रामों की संख्या नगरो से अधिक है । अभी भी भारत की लगभग अस्सी प्रति ात जनसंख्या गांव में निवास कर रही है । **महात्मा गॉधी ने ठीक कहा था** कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । जहा का मुख्य व्यवसाय कृषि है । इसी प्ररिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ग्रामीण कृषि का अध्ययन महत्व रखता है । जिसके माध्यम से हम भारतीय ग्रामण कृषि संरचना को समझा सकते है । इसी को ध्यान में रखकर इस शोध–पत्र में अध्ययन किया गया है । इस तारतम्य में कृषि के अन्तर्गत अध्ययन की जाने वाली सामग्री क्या है । तथा इसका विकास एवं उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

भारत में फसलों का ढॉचा :– कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन और उत्पादकता का अलग अर्थ होता है । उत्पादकता से तात्पर्य ''प्रति वर्ग हेक्टर में उत्पादित होने वाली फसल की कुल मात्रा से है'' जबकि उत्पादन से तात्पर्य दे ा में कुल खाद्यान्न उत्पादन से होता है ।

प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (कि.ग्रा.में)

फसल	1960–61	2000–01	2014–15
चावल	1013	1901	2390
गेहूँ	851	2708	2872
ज्वार	533	764	953
बाजरा	286	686	1272
मक्का	296	1822	2537
दालें	539	544	744
कुल खाद्यान्न	710	1625	2070
तिलहन	507	810	1037
कपास	125	190	461
पटसन	1049	2025	2627

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

स्त्रोतः— म्बवदवउपब ैवतअमल. 2015.16

2015—16 जैसा की सारणी से स्पष्ट है सभी खाद्यान्नों की कुल उत्पादिकता 1960—61 में 701 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी जो 2014—15 में बढ़कर 2070 कि.ग्रा. हो गई अर्थात इसमें 3 गुणा बड़ी वृद्धि हुई । पिछले 60 वर्षो में सबसे अधिक उत्पादकता में वृद्धि गेहूँ में उत्पादकता में हुई जो 1960—61 में 851 से बढ़कर 2014—15 में 2872 कि.ग्राम प्रति हेक्टर हो गई । तिलहनों की उत्पादकता में भी तेजी से वृद्धि हुई है । सबसे अधिक वृद्धि कपास के उत्पादन में देखी गई ।

कृषि को निर्धारित करने वाले कारकः— किसी भी देश में कृषि को निर्धारित करने वाले कई कारक होते है । जिन्हें हम प्राकृतिक सामाजिक, एतिहासिक व आर्थिक कारकों के अन्तर्गत वर्गीकृत कर सकते है । इसके अलावा, सरकार की कृषि संबंधी नीतियों और योजनाएं भी कृषि के पैटर्न को निर्धारित करती है ।

कारक :—

- प्राकृतिक कारक
- ऐतिहासिक कारक
- आर्थिक कारक
- सामाजिक कारक

ग्रामीण कृषि संरचना के सुधार मे हरित क्रान्ति :— हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है । हरित क्रन्ति में जहा एक ओर कृषि उत्पादकता की वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया वही कृषि क्षेत्र की परम्परागत उत्पादन तकनीक में संरचनात्मक परिवर्तन करने के प्रयास सम्मिलित किए गए इसके अलावा ग्रामीण कृषि के सुधार में बहु—फसलीय कार्यक्रम अपनाकर एक वर्ष में कई फसले उगाकर हरित क्रान्ति लाई गई । इस प्रकार कृषि संरचना में अमूल परिवर्तन लाया गया ।

घटक :—

- आर्थिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग ।
- रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
- बहु—फसलीय — कार्यक्रम
- पौध संरक्षण
- लघु सिंचाई परियोजना
- ग्रामीण कृषि को बढ़ावा
- विद्युतीकरण एवं परिवहन
- शिक्षा का विस्तार एवं कृषि अनुसंधान

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) :— सार्वजनिक निवे ा को बढ़ाने के लिए राज्यो को प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारवी योजना के लिए 25000 करोड़ में परिव्यय के साथ—वर्ष 2007—08 में (आरकेवीवाई) योजना शुरू की गई । ताकि योजना के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में 4.1 प्रति ात की वृद्धि दर प्राप्त की जा सकें । तीन वर्ष की अवधि वर्ष 2007—10 के दौर इस योजना के तहत 7895 करोड़ की रा ि। कृषि विकास हेतु जारी की गई ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) :— यह योजना अगस्त 1998 में आरम्भ की गई । सितम्बर 2010 तक लगभग 970.64 लाख केसीसी जारी किए गए है । इस योजना में उधार ऋण के माध्यम से किसानो को पर्याप्त और समय पर उनकी कृषि संबधी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान किया जा सकें ।

राष्ट्रीय बॉस मिशन :— बॉस फसल की सम्भावना को देश मे उपयोग करने के दृष्टिकोण से कृषि मंत्रालय देश की 27 राज्यों में केन्द्र

प्रायोजित एनबीएम को 568.23 करोड़ की कुल लागत से कार्यान्वित कर रहा है । इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र आधारित क्षेत्रवार भिन्न–भिन्न कार्य योजनाएं अपनाकर बॉस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास और बॉस कृषि और विपणन के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना है ।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन :– योजना का कार्यान्वयन देश के 372 जिलों में किया जा रहा है । वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान चिन्हित बागवानी फसलों का अतिरिक्त 16.57 लाख हेक्टर क्षेत्र शामिल किया गया । बागवानी फसलों की जैव कृषि 1.37 लाख हेक्टर क्षेत्र में अपनाई गई है ।

अन्य योजना विकास से संबंधित :–

- फसल बीमा योजना
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
- किसान काल सेन्टर
- कृषि उपज मूल्य नीति

कृषि में राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस योजना :– इस योजना का उद्दे य किसानों , सामान्य सेवा केन्द्रों, इन्टरनेट की ओस्क और एसएमएस सहित विविध माध्यमों से किसानों को उनके विकास से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।

निष्कर्षः– स्वतंत्रता के समय कृषि परम्परागत तरीके से की जाती थी, एस समय न तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता था, और न ही उन्नत बीज थें । कृषि मुख्य तौर पर जीवन–यापन के लिए होती थी । वाणिज्यिक स्तर पर नही इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है । स्वतंत्रता के समय कृषि को समझने के लिए हमे उस समय के ग्रामों में व्यापक ऋणग्रस्तता, महाजनी पूँजी की भूमिका, भूमि संबंधों कृषि जातों के आकार, सिंचाई की सुविधाओं, कृषि तकनीकों इत्यादि पर विचार करना होगा । कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और किसानों के प्रयासों से साठ के द ाक में कृषि क्षेत्र में शानदानर सफलता प्राप्त करने में मदद् मिली थी जिसे हरित क्रान्ति प्रमुखता से जाना गया था । पूर्ववर्ती वर्षा में प्राप्त उच्च कृषि उत्पादन और उत्पादकता ने काफी हद तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई है ।

संदर्भः–

- ग्रामीण एवं नगरीय समाजः– डॉ. अशोक डी पाटिल, 2016
- भारतीय अर्थव्यवस्था :– डॉ. माया राठी :– म. प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 2015
- भारतीय अर्थव्यवस्था :– डॉ. ऋतु तिवारी :– म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 2015
- यू.जी.सी. नेटः– अरिहन्त पब्लिकेशन्स , नई दिल्ली
- कृषि बेवसाईट